



राजपत्र, हिमाचल प्रदेश (असाधारण)

हिमाचल प्रदेश राज्यशासन द्वारा प्रकाशित

शिमला, बोरदार, 25 नवम्बर, 1993/4 मगहायण, 1915

हिमाचल प्रदेश सरकार

बिधि विभाग
(राजभाषा अनुभाग)

अधिसूचना

शिमला-2, 2 नवम्बर, 1993

सं० एम० एच० धार०(राजभाषा)बी०(१६)-८/९३.—भारत के राष्ट्रपति, हिमाचल प्रदेश राजभाषा (अनुपूरक उपबन्ध) अधिनियम, १९८१ (१९८१ का १२) की धारा ३ द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए "हि हिमाचल प्रदेश अन्त्योदय कारपोरेशन ऐक्ट, १९७९ (१९७९ का १७)" के, संलग्न अधिप्रमाणित राजभाषा

रूपान्तर को एतद्वारा राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित करने का आदेश देते हैं। यह उक्त अधिनियम का राजभाषा (हिन्दी) में प्राधिकृत पाठ समझा जाएगा और इसके परिणामस्वरूप भविष्य में उक्त अधिनियम में कोई संशोधन करना अपेक्षित हो तो यह राजभाषा में करना अनिवार्य होगा।

हस्ताक्षरित/-

सचिव (विधि)।

हिमाचल प्रदेश अन्त्योदय निगम अधिनियम, 1979

(1979 का 17)

(31-12-92 को यथा विद्यमान)

हिमाचल प्रदेश अन्त्योदय निगम की स्थापना करने का उपबन्ध करने के लिए अधिनियम ।

भारत गणराज्य के तीसवें वर्ष में हिमाचल प्रदेश राज्य विधान सभा द्वारा निर्मललिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

अध्याय 1

प्रारम्भिक

1. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश अन्त्योदय निगम अधिनियम, 1979 है । संक्षिप्त नाम ।
2. इस अधिनियम में, जब तक कि कोई बात विषय या सदर्थ में विरुद्ध न हो, — परिभाषाएं
 - (क) “कृषि विकास” के अन्तर्गत कृषि, औद्यानिकी, वानिकी, दुग्ध उद्योग, कुक्कुट पालन, सूअर पालन, भेड़ और पशु प्रजनन, मत्स्य पालन, रेशम उत्पादन विकास और सहवृद्ध उपव्यवसाय हैं ;
 - (ख) “अन्त्योदय कुटुम्ब” से राज्य सरकार द्वारा राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना में विहित मानदण्ड के अनुसार सक्षम प्राधिकारी द्वारा, इस रूप में पहचान किया गया कुटुम्ब और उसके सदस्य अभिप्रेत हैं ;
 - (ग) बैंक से निम्नलिखित अभिप्रेत है,—
 - (1) बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (1949 का 10) में यथा परिभाषित बैंककारी कम्पनी ;
 - (2) भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम, 1955 (1955 का 23) के अधीन गठित भारतीय स्टेट बैंक ;
 - (3) भारतीय स्टेट बैंक (समनुषंगी बैंक) अधिनियम, 1959 (1959 का 38) में यथा परिभाषित समनुषंगी बैंक ;
 - (4) प्रादेशिक ग्रामीण बैंक अधिनियम, 1976 (1976 का 21) के अधीन स्थापित प्रादेशिक ग्रामीण बैंक ;
 - (5) बैंककारी कम्पनी (उपक्रमों का अर्जन और अन्तरण) अधिनियम, 1970 (1970 का 5) के अधीन गठित तत्स्थानी नया बैंक ;
 - (6) बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (1949 का 10) की धारा 51 के अधीन भारत सरकार द्वारा अधिसूचित कोई बैंककारी संस्था ;
 - (7) कृषिक पुनर्वित्त और विकास निगम अधिनियम, 1963 (1963 का 10) के अधीन गठित कृषिक पुनर्वित्त और विकास निगम ;
 - (8) हिमाचल प्रदेश कृषिक उधार सन्क्रिया और प्रकीर्ण उपबन्ध (बैंक) अधिनियम, 1972 (1973 का 7) की धारा 2 के खण्ड (ग) में यथा परिभाषित कृषि-उद्योग निगम ;

- (9) कम्पनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) के अधीन निगमित कम्पनी कृषि वित्त निगम सीमित;
- (10) इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए राज्य सरकार द्वारा राजपत्र में बैंक के रूप में अधिसूचित कोई अन्य वित्तीय संस्था;
- (घ) "बोर्ड" से निगम का निदेशक बोर्ड अभिप्रेत है;
- (ङ) "अध्यक्ष" और "उपाध्यक्ष" से निगम का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष अभिप्रेत है;
- (च) "समिति" से इस अधिनियम की धारा 6 (2) के अधीन नियुक्त समिति अभिप्रेत है;
- (छ) "सक्षम प्राधिकारी" से ऐसा अधिकारी अभिप्रेत है जिसे इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए राज्य सरकार द्वारा विशेष रूप से सशक्त किया गया है;
- (ज) "निगम" से इस अधिनियम की धारा 3 के अधीन स्थापित हिमाचल प्रदेश अन्त्योदय निगम अभिप्रेत है;
- (झ) "केन्द्रीय सरकार" से भारत सरकार अभिप्रेत है;
- (ञ) "निदेशक" से बोर्ड का निदेशक अभिप्रेत है और इसके अन्तर्गत अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष भी हैं;
- (ट) "सीमान्त धन" से वित्तीय बैंककारी संस्थाओं और अन्य संगठनों द्वारा वित्तीय सहायता देने के लिए लाभग्राही के अंश के रूप में अपेक्षित धन-अभिप्रेत है;
- (ठ) "विपणन" से कृषि या औद्योगिक उत्पाद, चाहे वह प्राथमिक रूप में हो या अर्द्ध-प्रसंस्कृत अथवा प्रसंस्कृत रूप से हो, के परिवहन, श्रेणीकरण, एकत्रीकरण, विपणन और बिक्री से सम्बन्धित सभी क्रियाकलाप अभिप्रेत हैं;
- (ड) "विहित" से इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा विहित अभिप्रेत है;
- (ढ) "प्रसंस्करण" से कृषि उपज को विपण्य या उपभोग के लिए उपयुक्त बनाने के प्रसंस्करण से सम्बन्धित सभी क्रियाकलाप अभिप्रेत हैं, और इसके अन्तर्गत कच्चे माल का कय और भण्डारण, उपस्कर का कय और परिसाधित उपज के ऐसे प्रसंस्करण और भण्डारण के लिए अपेक्षित मशीनरी का कय, प्रतिष्ठापन और चलाया जाना भी है;
- (ण) "लघु उद्योग" से समस्त कुटीर और लघु उद्योग अभिप्रेत हैं जिसके अन्तर्गत घरेलू उद्योग भी हैं जहाँ गृहस्थी के सदस्य विभिन्न प्रकार के माल, मशीनरी और उपस्करों के विनिर्माण, मरम्मत, अनुरक्षण और निर्माण में लगे हुए हैं;
- (त) "राज्य सरकार" से हिमाचल प्रदेश सरकार अभिप्रेत है; और
- (थ) "व्यापार और कारोबार" से वाणिज्यिक क्रियाकलाप अभिप्रेत हैं जिसमें आर्थिक लाभ के लिए माल और अन्य बिक्रय योग्य वस्तुओं का बिक्रय, कय और विनिर्माण शामिल है ।

अध्याय 2

हिमाचल प्रदेश अन्त्योदय निगम का निगमन और इसकी पूंजी

हिमाचल प्रदेश
अन्त्योदय
निगम की
स्थापना ।

3. (1) राज्य सरकार, इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए अधिसूचना द्वारा ऐसी तारीख से जो यह इस निमित निर्दिष्ट करे, हिमाचल प्रदेश अन्त्योदय निगम के नाम से ज्ञात निगम स्थापित कर सकेगी ।

(2) निगम पूर्वोक्त नाम से एक निगमित निकाय होगा जिसका शाश्वत उत्तराधिकार और सामान्य मुद्रा होगी, और इसे इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन रहते हुए सम्पत्ति का अजन, धारण और व्यय करने और संविदा करने की शक्ति होगी तथा उक्त नाम से वह ऋण ले सकेगा और उस पर ऋण लिया जा सकेगा।

(3) यदि राज्य सरकार का समाधान हो जाता है कि निगम ने या तो उस पर इस अधिनियम द्वारा या उसके अधीन अधिरोपित किसी कर्तव्य का पालन करने में व्यतिक्रम किया है या लोकहित में ऐसा करना समीचीन है, तो राज्य सरकार, अधिनियम में किसी बात के प्रतिकूल होते हुए भी, राजपत्र में प्रकाशित लिखित आदेश द्वारा निगम को अधिकांत कर सकेगी।

(4) निगम के अधिक्रमण के पश्चात् और जब तक इसे पुनर्गठित नहीं किया जाता है, इस अधिनियम के अधीन निगम और उसके बोर्ड के कर्तव्य और कृत्य राज्य सरकार द्वारा या ऐसे अधिकारी अथवा अधिकारियों द्वारा किए जाएंगे जो राज्य सरकार द्वारा इस प्रयोजन के लिए नियुक्त किए जाएं।

(5) पूर्ववर्ती उप-धाराओं या इस अधिनियम में किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी राज्य सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा घोषणा कर सकेगी कि ऐसी तारीख से जो अधिसूचना में विनिर्दिष्ट की जाए, निगम विघटित कर दिया जाएगा।

(6) उप-धारा (5) के अधीन अधिसूचना में विनिर्दिष्ट तारीख से—

(क) सभी सम्पत्तियाँ, निधि और देय जो निगम में निहित हैं या उस द्वारा बसूलीयोग्य हैं, राज्य सरकार में निहित और बसूली योग्य होंगे;

(ख) निगम के विरुद्ध प्रवर्तनीय सभी दायित्व राज्य सरकार में निहित या उस द्वारा बसूल की गई सम्पत्तियों, निधियों और देयों के विस्तार तक, राज्य सरकार के विरुद्ध प्रवर्तनीय होंगे।

4. (1) निगम का मुख्यालय शिमला या ऐसे अन्य स्थान पर होगा जो राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट करे।

निगम का मुख्यालय।

(2) निगम हिमाचल प्रदेश के भीतर या बाहर अपने उप-कार्यालय या एजेंसियाँ ऐसे स्थानों पर स्थापित कर सकेगा जो यह ठीक समझे।

5. (1) निगम की पूंजी पाँच करोड़ रुपये से अनधिक ऐसी राशि होगी, जैसी राज्य सरकार निश्चित करे:

निगम की पूंजी

परन्तु जहाँ प्रारम्भ में निश्चित पूंजी पाँच करोड़ रुपये से कम है, वहाँ राज्य सरकार, समय-समय पर, पूंजी की पाँच करोड़ रुपये से अनधिक की ऐसी राशि तक बढ़ा सकेगी, जो यह ठीक समझे।

(2) राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर, ऐसे निर्बन्धनों और शर्तों के अधीन रहते हुए, ऐसी पूंजी का प्रावधान किया जा सकेगा जैसी अवधारित की जाए।

स्पष्टीकरण.—इस धारा के प्रयोजन के लिए “पूंजी” पद के अन्तर्गत निगम द्वारा विनिर्दिष्ट, प्रयोजन (प्रयोजनों) के लिए प्राप्त सहायता अनुदान, सहायकी या दान नहीं है।

अध्याय 3

निगम का प्रबन्ध

प्रबन्ध ।

6. (1) निगम के कार्यकलाप और कारखार का सामान्य अधीक्षण, निदेशन और प्रबन्ध बोर्ड में निहित होगा जो ऐसी सभी शक्तियों का प्रयोग कर सकेगा और ऐसे सभी कार्य तथा बातें कर सकेगा जो इस अधिनियम के अधीन निगम द्वारा प्रयोग और की जा सकती हों।

(2) इस निमित्त बनाए गए किन्हीं नियमों के अधीन रहते हुए, बोर्ड, अपने कृत्यों के दक्ष निर्वहन को सुनिश्चित करने के प्रयोजन के लिए, समय-समय पर एक या अधिक समितियां नियुक्त कर सकेगा।

(3) बोर्ड अपने कृत्यों का निर्वहन करते समय ऐसे सिद्धान्तों पर कार्य करेगा जो लोकहित, अन्त्योदय कुटुम्बों का कल्याण और निगम की ऋण शोध क्षमता को, ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार की नीति के अनुकूल होंगे और नीति के प्रश्न पर इसका मार्गदर्शन ऐसे अनुदेशों द्वारा किया जाएगा जो राज्य सरकार द्वारा इसे दिए जाएं।

(4) यदि कोई शंका उत्पन्न हो जाती है कि क्या कोई प्रश्न नीति का प्रश्न है या नहीं, उस पर राज्य सरकार का विनिश्चय अन्तिम होगा।

निदेशक बोर्ड ।

7. (1) बोर्ड नौ निदेशकों से गठित होगा जो राज्य सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट किए जाएंगे :

परन्तु मुख्य मंत्री, हिमाचल प्रदेश, बोर्ड का पदेन निदेशक और अध्यक्ष होगा :

परन्तु यह और कि कम से कम दो निदेशक ऐसे व्यक्तियों में से नामनिर्दिष्ट किए जाएंगे जो हिमाचल प्रदेश की ग्रामीण परिस्थितियों का विशेष ज्ञान और अन्त्योदय कुटुम्बों के उत्थान में अभिरूचि रखते हों :

परन्तु यह और कि यदि ऐसा करना समीचीन हो तो, राज्य सरकार निदेशकों में से किसी एक को बोर्ड का उपाध्यक्ष नाम निर्दिष्ट कर सकेगी और वह ऐसे कर्तव्यों का पालन और ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगा जो बोर्ड द्वारा अधिनियम की धारा 15 की उप-धारा (3) के अधीन, यथास्थिति, उसको समनुद्दिष्ट या प्रदत्त की जाएं।

(2) निदेशक या उपाध्यक्ष के पद में, मृत्यु, त्याग-पत्र के कारण या अन्यथा, कोई रिक्ति होने पर, उसे राज्य सरकार द्वारा, उप-धारा (1) में उपबन्धित रीति में भरा जाएगा।

(3) इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, निदेशकों और उपाध्यक्ष की नियुक्ति के निवन्धन और शर्तें और उनको संदेय फीस और भत्ते, ऐसे होंगे जैसे विहित किए जाएं।

पदावधि ।

8. अध्यक्ष और प्रबन्ध निदेशक से भिन्न निदेशकों की पदावधि तीन वर्ष होगी और वे पुनर्नियुक्ति के लिए पात्र होंगे।

9. कोई भी व्यक्ति निदेशक के रूप में नाम निदिष्ट किए जाने और बने रहने लिए निर्धारित होगा :—

निदेशक के पद के लिए निरहताएँ ।

- (क) यदि वह दिवालिया है या किसी भी समय दिवालिया न्याय-निर्णीत किया गया है अथवा उसने अपने ऋण का संदाय निलम्बित किया है या अपने लेनदारों के साथ समझौता किया है;
- (ख) यदि वह विवृत चित्त है और सक्षम न्यायालय द्वारा ऐसा घोषित कर दिया गया है;
- (ग) यदि वह किसी ऐसे अपराध का दोषमिद्ध है या ठहराया गया है जो राज्य सरकार की राय में नैतिक अधमता से अन्तर्गस्त है; या
- (घ) यदि उसे किसी राज्य सरकार या केन्द्रीय सरकार अथवा किसी राज्य सरकार या केन्द्रीय सरकार के स्वामित्वधीन या नियन्त्रणाधीन किसी निगमित निकाय की सेवा से हटा दिया गया है या पदच्युत कर दिया गया है ।

10. निदेशक बोर्ड या उसकी समिति की किसी बैठक में विचार के लिए आए किसी विषय की जिस में उसका प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः कोई आर्थिक हित हो, सुसंगत परिस्थितियों को उसकी जानकारी में आने के पश्चात्, यथा शक्य शीघ्र, ऐसी बैठक में अपने हित के स्वरूप को प्रकट करेगा और प्रकटीकरण को, यथास्थिति, बोर्ड या समिति के कार्यवृत्त में अभिलिखित किया जाएगा और निदेशक उस विषय के बारे में बोर्ड या समिति के विचार-विमर्श या विनिश्चय में कोई भाग नहीं लेगा ।

कुछ मामलों में निदेशक द्वारा भाग न लेना ।

11. (1) राज्य सरकार, किसी भी समय, किसी भी निदेशक को पद से हटा सकेगी, यदि इस की राय में ऐसा निदेशक —

हटाया जाना और त्याग-पत्र ।

- (क) धारा 9 में वर्णित किसी निरहता के अधीन है या हो गया है;
- (ख) बोर्ड की अनुमति के बिना, उसकी तीन से अधिक आनुक्रमिक बैठकों से बोर्ड की राय में, उसकी अनुपस्थिति माफ करने के लिए पर्याप्त हेतु के बिना, अनुपस्थित है;
- (ग) धारा 10 के उपबन्धों के उल्लंघन में कार्य किया है; या
- (घ) किसी अन्य कारण से दोषी पाया गया है जिसे बोर्ड द्वारा पर्याप्त समझा जाए :

परन्तु प्रस्तावित आदेश के विरुद्ध कारण वर्णित करने का युक्तियुक्त अवसर दिए बिना निदेशक को हटाए जाने का आदेश पारित नहीं किया जाएगा ।

(2) निदेशक, लिखित में राज्य सरकार को उसका नोटिस देते हुए अपने पद का त्याग कर सकेगा और ऐसे त्याग-पत्र के स्वीकार किए जाने पर उस द्वारा अपना पद रिक्त कर दिया समझा जाएगा ।

12. (1) बोर्ड ऐसे समय और स्थानों पर बैठक करेगा और अपनी बैठकों में कारबार के सञ्चालन के सम्बन्ध में प्रक्रिया के ऐसे नियमों का (जिसके अन्तर्गत बैठकों में गण-पूति भी है) अनुपालन करेगा जैसे इस अधिनियम के अधीन निगम द्वारा बनाए गए विनियमों द्वारा उपबन्धित किए जाएँ ।

बैठकें ।

(2) अध्यक्ष, और उसकी अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष, और दोनों की अनुपस्थिति में

निदेशकों द्वारा अपने में से निर्वाचित कोई अन्य निदेशक, बोर्ड की प्रत्येक बैठक की अध्यक्षता करेगा।

(3) बोर्ड की किसी बैठक में उसके समक्ष आने वाले सभी प्रश्नों का विनिश्चय उपस्थित और मत देने वाले निदेशकों के बहुमत द्वारा किया जाएगा, और मत बराबर होने की दशा में, यथास्थिति, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष या अध्यक्षता करने वाले व्यक्ति का दूसरा या निर्णायक मत होगा और वह इस का प्रयोग करेगा।

प्रबन्ध निदेशक । 13. (1) राज्य सरकार, निदेशकों में से एक को, राज्य सरकार का अधिकारी होने के नाते, प्रबन्ध निदेशक के रूप में नियुक्त करेगी जो इसके प्रसाद-पर्यंत पद धारण करेगा।

(2) निगम का प्रबन्ध निदेशक --

- (क) इसका मुख्य कार्यपालक अधिकारी होगा,
- (ख) निगम के कार्यचालन प्रबन्ध और बोर्ड द्वारा अनुमोदित सामान्य नीतियों के कार्यान्वयन के लिए उत्तरदायी होगा;
- (ग) ऐसे कर्तव्यों का पालन करेगा जैसे बोर्ड विनियमों द्वारा या अन्यथा उसे समनुदेशित करे;
- (घ) ऐसा वेतन और भत्ते प्राप्त करेगा और सेवा के ऐसे निबन्धनों और शर्तों से शासित होगा जैसे बोर्ड द्वारा अवधारित और राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित की जाएं।

(3) यदि प्रबन्ध निदेशक अंग-शैथिल्य द्वारा या अन्यथा अपने कर्तव्यों का पालन करने में असमर्थ हो जाता है या छुट्टी पर अन्यथा है या अन्यथा ऐसी परिस्थितियों में अनुपस्थित है जिनमें उसके पद का रिक्त होना अन्तर्बलित नहीं है, तो राज्य सरकार उसकी अनुपस्थिति के दौरान उसके स्थान पर दूसरा निदेशक, जो राज्य सरकार का अधिकारी है, नियुक्त कर सकेगी।

नियुक्ति में त्रुटि से कार्यो आदि का अविधिमान्य न होना । 14. (1) बोर्ड या इस की किसी समिति का कोई कार्य या कार्यवाही केवल, यथा-स्थिति, बोर्ड या समिति में विद्यमान रिक्ति या इसके गठन में किसी त्रुटि के आधार पर प्रश्नगत या अविधिमान्य नहीं होगा।

(2) किसी भी व्यक्ति द्वारा निदेशक या किसी समिति के सदस्य के रूप में सद्-भाक्पूर्वक किया गया कोई कार्य, केवल उस आधार पर कि वह निदेशक या सदस्य होने के लिए निरहित था या उसके नाम निर्देशन में कोई अन्य त्रुटि थी, अविधिमान्य नहीं समझा जाएगा।

निगम के अधिकारी और अन्य कर्मचारी । 15. (1) बोर्ड, निगम के कृत्यों के दक्षतापूर्ण पालन के लिए ऐसे अधिकारी और कर्मचारी नियुक्त कर सकेगा, जो यह आवश्यक समझे और विनियमों द्वारा या अन्यथा उन की नियुक्ति और सेवा की शर्तें और उन की संदेय पारिश्रमिक अवधारित कर सकेगा।

(2) बोर्ड, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़े वर्ग और अन्त्योदय कुटुम्बों के सदस्यों के पक्ष में निगम के अधीन सेवा में नियुक्तियों और पदों में आरक्षण के बारे में ऐसे सदस्यों को पर्याप्त प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के लिए, ऐसे निदेशों का पालन करेगा, जैसे समय-समय पर, राज्य सरकार द्वारा जारी किए जाएं।

(3) बोर्ड, साधारण या विशेष आदेश द्वारा, निगम के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, प्रबन्ध निदेशक, निदेशक या किसी अन्य अधिकारी अथवा कर्मचारी को ऐसी शर्तों और परि-सीमाओं के अधीन रहते हुए, यदि कोई हों, जो विनिर्दिष्ट की जाएं, इस अधिनियम के अधीन अपनी ऐसी शक्तियों और कर्तव्यों को, विनियम बनाने की शक्ति को छोड़ कर, जो वह आवश्यक समझे, प्रत्यायोजित कर सकेगा।

अध्याय 4

निगम के कृत्य और निधियां

16. (1) इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, अन्त्योदय कुटुम्बों के उत्थान का कार्य अपने हाथों में लेना निगम का प्रथम कर्तव्य होगा। निगम के कृत्य।

(2) पूर्वगामी उपबन्धों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे कृत्यों के अन्तर्गत निम्नलिखित कृत्य होंगे—

- (1) कृषि विकास, कृषि उपज का विपणन, प्रसंस्करण, प्रदाय और भण्डार-करण, लघु कुटीर और ग्रामोद्योग, व्यापार और कारवार या किसी अन्य क्रियाकलाप के कार्यक्रमों की स्वयं या अन्य अभिकरणों, चाहे सरकारी या गैर-सरकारी, के सहयोग या माध्यम से योजना बनाना, संप्रवर्तन और प्रारम्भ करना जो, बोर्ड की राय में, अन्त्योदय कुटुम्बों के सदस्यों को बेहतर आजीविका उपार्जित करने और उनकी आर्थिक दशा के उत्थान में सहायता करने में समर्थ बनाएंगे;
- (2) वित्तीय, तकनीकी और प्रबन्धकीय सहायता और किसी अन्य सहायता की व्यवस्था करके जो इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए अपेक्षित हो, रोजगार मूलक उद्योग स्थापित करने के लिए कार्यक्रम प्रारम्भ करना;
- (3) अन्त्योदय कुटुम्बों के सदस्यों को उधार देकर या उसकी व्यवस्था कर के और किन्हीं प्रयोजनों के लिए अन्तर धन संदत्त करके वित्तीय सहायता की व्यवस्था करना जिससे ऐसे कुटुम्बों को आय पैदा होगी;
- (4) अन्त्योदय कुटुम्बों के फायदे के लिए अन्त्योदय कुटुम्बों के सदस्यों और ऐसे ही अन्य संगठनों को अनुदान और सहायकी देना और उन द्वारा लिए गए उधार की प्रत्याभूति देना;
- (5) अन्त्योदय कुटुम्बों के सदस्यों को लाभकर रोजगार उपलब्ध कराने की दृष्टि से कौशलता के प्रशिक्षण का प्रबन्ध करना;
- (6) अन्त्योदय कुटुम्बों को नकद या वस्तु रूप में सहायता के वितरण के लिए राज्य सरकार या केन्द्रीय सरकार के अभिकरण के रूप में कार्य करना;
- (7) अन्त्योदय कुटुम्बों द्वारा विनिर्मित तैयार माल के प्रचार और विपणन की व्यवस्था करना;
- (8) वाणिज्यिक बैंकों या किसी अन्य संगठन से, जिसके अन्तर्गत सरकार भी है, ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए जैसी बोर्ड विनिर्दिष्ट करे, धन उधार लेना;

- (9) दान, अनुदान और सदान प्राप्त करना और बन्धपत्र और डिबेन्चर जारी करना;
- (10) वचनपत्र, विनिमयपत्र, हुण्डियां, बिल, वारण्ट, डिबेन्चर और अन्य पर-क्राम्य लिखतों को लिखना, बनाना, स्वीकार करना, पृष्ठांकित करना, छूट देना, निष्पादित और जारी करना;
- (11) निगम की अधिशेष निधियों की सरकारी प्रतिभूतियों या ऐसी अन्य रीति में जो बोर्ड विनिश्चय करे, विनिहित और निक्षेपित करना;
- (12) संविदाएं करना;
- (13) अन्त्योदय कुटुम्बों के उत्थान से सम्बन्धित समस्याओं के सम्बन्ध में उनके सदस्यों को लाभकारी रोजगार उपलब्ध करवाने की दृष्टि से सर्वेक्षण, अनुसन्धान और अध्ययन की सुविधाएं प्रदान करना;
- (14) ऐसे अन्य कृत्य प्रारम्भ करना जो इस अधिनियम और तद्धीन बनाए गए नियमों के अधीन उस पर प्रदत्त किन्हीं कृत्यों के अनुपूरक, आनुषंगिक या पारिणामिक हैं; और
- (15) ऐसे अन्य कार्यक्रमों को प्रारम्भ करना और ऐसे अन्य कृत्यों का निर्वहन करना जैसे राज्य सरकार, समय-समय पर, विहित करे।

निगम की
निधियां।

17. निगम निम्नलिखित निधियां स्थापित करेगा और रखेगा, अर्थात्:—

- (क) विकास और वित्त निधि;
- (ख) प्रत्याभूति और डूबंत ऋण निधि;
- (ग) राहत और सामूहिक हित निधि;
- (घ) सहायता अनुदान और सहायकी निधि, और
- (ङ) ऋण निधि।

विकास और
वित्त निधि।

18. धारा 19, 20, 21 और 22 में अन्यथा उपबन्धित के सिवाय,—

- (1) सभी रकम, जो निगम द्वारा किसी स्रोत से, जो भी हो, प्राप्त की जाती है, विकास और वित्त निधि में जमा की जाएंगी।
- (2) सभी रकमों, जो निगम द्वारा व्यय की जाती है, इस निधि में से विकलित की जाएंगी।

प्रत्याभूति
और डूबंत
ऋण निधि।

19. (1) प्रत्याभूति और डूबंत ऋण निधि का गठन निम्नलिखित से होगा —

- (1) राज्य सरकार द्वारा इस प्रयोजन के लिए अनुदान के रूप में निगम के व्ययन पर रखी निधियां;
- (2) इसके अपने लाभ का दस प्रतिशत;
- (3) इस निधि पर, समय-समय पर, प्रोदभूत व्याज;
- (4) ऐसा धन, जिसका विनिर्दिष्टतः किसी अभिकरण, संगठन और स्वयं निगम द्वारा इस निधि में अभिदाय किया जाए, जैसा कि बोर्ड द्वारा विनिश्चित किया जाए;

परन्तु इस की कोई भी बात राज्य सरकार, केन्द्रीय सरकार या किसी अन्य संगठन या अभिकरण को अनुदान या दान के रूप में इस निधि में विकलित की जाने के लिए ऐसी रकम देने से वर्जित करने वाली नहीं समझी जाएगी।

(2) इस निधि का अन्त्योदय कुटुम्बों के सदस्यों या संगठनों द्वारा लिए गए उधारों के बारे में प्रत्याभूति देने के सम्बन्ध में और निगम के अवसूलीय ऋण को ऐसी रीति में चुकाने के लिए जो विहित की जाए, उपयोग किया जाएगा।

20. (1) राहत और सामूहिक हित निधि में प्रत्येक वर्ष निगम के शुद्ध लाभ के दस प्रतिशत से अनधिक, के यदि कोई हो, ऐसी रकम जमा की जाएगी, जैसी बोर्ड विनिश्चित करे;

राहत और सामूहिक हित निधि ।

परन्तु इसकी कोई भी बात, राज्य सरकार, केन्द्रीय सरकार या किसी अन्य संगठन को अतिरिक्त अनुदान के रूप में इस निधि में जमा की जाने के लिए, ऐसी रकम देने से, जो यह ठीक समझे, वर्जित करने वाली नहीं समझी जाएगी ।

(2) राहत और सामूहिक हित निधि को, ऐसे रूप और रीति में जैसी बोर्ड द्वारा विनिश्चित की जाए, अन्योदय कुटुम्बों के सदस्यों के कल्याण में सम्बन्धी प्रयोजनों के लिए उपयोग किया जाएगा ।

21. सहायता अनुदान और सहायकी निधि में वे रकमें, जो राज्य सरकार, केन्द्रीय सरकार या किसी अन्य संगठन अभिकरण, से अन्योदय कुटुम्बों या संगठनों को अनुदान/सहायकी के रूप में उनके आर्थिक उत्थान के विनिर्दिष्ट प्रयोजन के लिए खर्च की जाने के लिए प्राप्त हों, जमा की जाएगी । इस निधि के उपयोग के लिए अनुदाता द्वारा अधिरोपित शर्तों का, यदि कोई हो, पालन किया जाएगा ।

सहायता अनुदान और सहायकी निधि ।

22. निगम द्वारा वित्तीय संस्थाओं/बैंकों और राज्य या केन्द्रीय सरकार अथवा किसी अन्य अभिकरण से लिए गए या अभिप्राप्त ऋण इस निधि में जमा किए जाएंगे । ऋण निधि का उपयोग, निगम के हित के संरक्षण के लिए, बोर्ड द्वारा यथा आवश्यकित ब्याज की दर पर और यथा अधिरोपित शर्तों पर, उधार देने के प्रयोजन के लिए दिया जाएगा ।

ऋण निधि ।

अध्याय 5

ऋण और अनुदान की वसूली

23. किसी करार में किसी बात के प्रतिकूल होते हुए भी, निगम, लिखित नोटिस द्वारा, किसी हिताधिकारी से जिसके अन्तर्गत प्रत्याभूति दाता और ऋणी भी है, उसकी सहायकी, अनुदान या किसी अन्य रूप में दी गई रकम का पूर्णतः या उसके किसी भाग का निम्नलिखित दशा में निगम को तत्काल उन्मोचन करने की अपेक्षा कर सकेगा —

अनुदान के पुनः ग्रहण और उधार का प्रति-संदाय मांगने की शक्ति ।

(क) यदि बोर्ड की यह प्रतीत होता है कि हिताधिकारी द्वारा, प्रसुविधा प्राप्त करने से पूर्व या उस समय, कोई मिथ्या या भ्रामक सूचना या विशिष्ट दी है;

(ख) यदि प्राप्तकर्ता निगम द्वारा संदाय के समय अधिरोपित ऐसे अनुदान, सहायकी या उधार के किन्हीं निबन्धनों का पालन करने में असफल रहा है;

(ग) यदि वह, निगम द्वारा, यथास्थिति ऐसा, उधार या अनुदान देते समय करार के किन्हीं उपबन्धों या अधिरोपित शर्तों का उल्लंघन करता है;

(घ) यदि व्यक्तिगत आशंका है कि हिताधिकारी धन का उस प्रयोजन के लिए उपयोग करने में असमर्थ है जिसके लिए यह दिया गया है; या

(ङ) यदि किसी अन्य कारण से निगम के हित का संरक्षण करने के लिए ऐसा करना आवश्यक है ।

निगम को
देयधन की
वसूली ।

24. (1) जहां किसी व्यक्ति से, जिसके अन्तर्गत ऋणी का प्रतिभू भी है, ऋण, अग्रिम, अनुदान, सहायकी या इस द्वारा दिए गए किसी वित्तीय स्रोत के बारे में निगम को कोई रकम देय है, वहां ऐसी रकम प्रबन्ध निदेशक द्वारा विहित प्ररूप में प्रमाण-पत्र जारी किए जाने पर, उस जिले के कलक्टर द्वारा, जिसमें वह व्यक्ति जिससे रकम देय है, निवास करता है या कारबार करता है अथवा किसी सम्पत्ति का स्वामी है, भू-राजस्व की बकाया के रूप में वसूली होगी ।

(2) उप-धारा (1) के अधीन प्रबन्ध निदेशक द्वारा जारी किया गया प्रमाण-पत्र अन्तिम और निश्चयक होगा और किसी प्राधिकारी या न्यायालय के समक्ष प्रश्नगत नहीं किया जाएगा ।

(3) ऋण या किसी अन्य अग्रिम के बारे में निगम को देय किसी राशि की वसूल करने के प्रयोजन के लिए, प्रतिभू के विरुद्ध कार्यवाही करने से पूर्व मालिक के विरुद्ध कार्यवाही करना आवश्यक नहीं होगा ।

निगम के
देयों का
प्रथम भार ।

25. तत्काल प्रवृत्त किसी विधि में किसी बात के होते हुए भी, किन्तु प्रभारों की पूर्विक्ता के सम्बन्ध में लोक सभा द्वारा बनाई गई किसी विधि के उपबन्धों और बैंक या सरकार के भू-राजस्व या इस द्वारा भू-राजस्व की बकाया के रूप में वसूली किसी धन के बारे में किसी पूर्विक् दावे के अधीन रहते हुए, इस अधिनियम की पूर्ववर्ती धारा के अधीन यथा अवधारित निगम के देय, उस पर प्रोदभत ब्याज और वसूली की लागत सहित, ऋणी और प्रत्याभूतिदाता, यदि कोई हो, का सम्पत्ति पर प्रथम भार होगा ।

अध्याय 6

लेखा और संपरीक्षा

लेखा ।

26. (1) तुलनपत्र और लेखा, जिसके अन्तर्गत निगम के लाभ और हानि लेखा भी है, ऐसे प्ररूप और रीति में तैयार और रखे जाएंगे जैसे विहित किए जाएं ।

(2) बोर्ड, प्रति वर्ष इक्कीस मार्च को निगम की बहियों और लेखों को संतुलित और बन्द करवाएगा ।

संपरीक्षा ।

27. (1) प्रत्येक वित्तीय वर्ष में एक बार निगम के लेखाओं की संपरीक्षा, कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 226 की उप-धारा (1) के अधीन संपरीक्षकों के रूप में कार्य करने के लिए सम्यक् रूप से अर्हित, संपरीक्षकों द्वारा की जाएगी जिन की नियुक्ति बोर्ड द्वारा की जाएगी, और निगम से ऐसा पारिश्रमिक प्राप्त करेंगे जो बोर्ड नियत करे ।

(2) संपरीक्षकों को निगम के वार्षिक तुलनपत्र और लाभ और हानि लेखा की प्रति दी जाएगी और उससे संबंधित लेखाओं और वाऊचरों के साथ उसकी परीक्षा करना उनका कर्तव्य होगा, और उन्हें निगम द्वारा रखी गई सभी बहियों की सूची परिदत्त की जाएगी तथा सभी युक्तियुक्त समयों पर निगम की बहियों, लेखाओं, वाऊचरों और अन्य दस्तावेजों तक उनकी पहुँच होगी और वे निगम के किसी निदेशक या अधिकारी से ऐसी जानकारी की अपेक्षा कर सकेंगे जैसी संपरीक्षक के रूप में अपने कर्तव्यों के पालन के लिए संपरीक्षक आवश्यक समझे ।

(3) संपरीक्षक, उन द्वारा परीक्षित वार्षिक तुलनपत्र और लेखाओं पर निगम को रिपोर्टें देंगे और ऐसी प्रत्येक रिपोर्ट में वे यह कथन करेंगे कि क्या उनकी राय में तुलनपत्र सभी आवश्यक विशिष्टियों से युक्त, पूर्ण और सही तुलनपत्र है और उचित रूप से तैयार किया गया है जिससे निगम के कार्यकलाप की स्थिति का सही और ऋजु चित्र प्रदर्शित होता है ।

(4) निगम अपने लेखाओं के बन्द और संतुलित किए जाने की तारीख से चार मास के भीतर संपरीक्षकों की रिपोर्ट की प्रति के साथ अपने तुलनपत्र और लेखाओं की प्रति और सुसंगत वर्ष के दौरान निगम के कार्यकरण की रिपोर्टें, राज्य सरकार को प्रस्तुत करेगा । राज्य सरकार इनको, यथाशक्य शीघ्र, विधान सभा के समक्ष, जब वह सत्र में हो, कुल दस दिन की अवधि के लिए रखेगी । यह अवधि एक सत्र में अथवा दो या अधिक आनुक्रमिक सत्रों में पूरी हो सकेगी ।

(5) पूर्वगामी उप-धाराओं की किसी बात पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, निगम के लेखाओं की, जब भी लोक हित में ऐसा करना आवश्यक और समीचीन समझा जाए, समय-समय पर, इस निमित्त राज्य सरकार द्वारा विशेष रूप से प्राधिकृत अभिकरण द्वारा भी संपरीक्षा की जा सकेगी और इस द्वारा ऐसे परीक्षण और रिपोर्टों के सम्बन्ध में उपगत कोई व्यय निगम द्वारा ऐसे अभिकरण को संदेय होगा ।

अध्याय 7

प्रकीर्ण

28. (1) इस अधिनियम से भिन्न, कम्पनी या निगम के परिसमापन, विघटन या समापन से सम्बन्धित विधि का कोई उपबन्ध निगम को लागू नहीं होगा । बोर्ड का विघटन ।

(2) राज्य सरकार, यदि निगम अपनी शक्तियों का अतिक्रमण करता है या धारा 27 के अधीन रिपोर्टें प्राप्त होने पर, बोर्ड से यह कारण दर्शित करने की अपेक्षा कर सकेगी कि इसे क्यों विघटित न किया जाए, और यदि विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर कोई स्पष्टीकरण पेश नहीं किया जाता है, या यदि राज्य सरकार का स्पष्टीकरण से समाधान नहीं होता है, तो यह बोर्ड को ऐसी तारीख से जो विनिर्दिष्ट की जाए विघटित कर सकेगी ।

29. (1) जब बोर्ड को धारा 28 के अधीन विघटित किया जाता है तब —

- (1) विघटन की तारीख से समस्त निदेशक अपने पद स्वतः कर देंगे;
- (2) विघटन की अवधि के दौरान, बोर्ड की सभी शक्तियों का प्रयोग और सभी कर्तव्यों का पालन ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों द्वारा किया जाएगा जिसे या जिन्हें राज्य सरकार इस निमित्त नियुक्त करे;
- (3) विघटन की अवधि के दौरान निगम में निहित सभी निधियों और अन्य सम्पत्ति राज्य सरकार में निहित हो जाएगी ।

बोर्ड के विघटन के परिणाम ।

(2) राज्य सरकार, स्वविवेकाधिकार से, ऐसी अवधि के पश्चात् जो यह ठीक समझे, बोर्ड का पुनर्गठन कर सकेगी ।

अधिकारिता
का वर्जन ।

30. इस अधिनियम में अभिव्यक्त रूप से जैसा अन्यथा उपबन्धित है, उसके सिवाय, किसी भी सिविल न्यायालय को, किसी भी विषय के बारे में, जिसे निगम या इस अधिनियम के अधीन नियुक्त कोई अधिकारी या प्राधिकारी इस अधिनियम द्वारा या इसके अधीन अवधारित करने को सशक्त है, कोई वाद या कार्रवाई ग्रहण करने की अधिकारिता नहीं होगी और किसी भी न्यायालय या अन्य प्राधिकारी द्वारा, इस अधिनियम द्वारा या उसके अधीन प्रदत्त किन्हीं शक्तियों के अनुमरण में की गई या की जाने वाली कार्रवाई के बारे में कोई व्यादेश मंजूर नहीं किया जाएगा ।

सद्भावपूर्वक
की गई कार-
वाई के लिए
संरक्षण ।

31. इस अधिनियम के अनुसरण में सद्भावपूर्वक की गई या की जाने के लिए आशयित किसी बात से हुई या हो साने वाली किसी हानि या नुकसान के लिए कोई भी वाद या अन्य विधिक कार्यवाही, निगम या प्रबन्ध निदेशक सहित किसी निदेशक, अथवा इस अधिनियम के अधीन निगम द्वारा किन्हीं कृत्यों के निर्वहन के लिए प्राधिकृत किसी अधिकारी या कर्मचारी अथवा किसी अन्य व्यक्ति के विरुद्ध नहीं होगी ।

अधिकारियों
और कर्म-
चारियों का
लोक सेवक
होना ।

32. प्रबन्ध निदेशक और निगम के अन्य कर्मचारी भारतीय दण्ड संहिता की धारा 21 के अर्थ के अन्तर्गत लोक सेवक समझे-जाएंगे ।

निदेशकों की
अतिपूर्ति ।

33. (1) निगम, प्रत्येक निदेशक को, ऐसी हानियों और व्ययों के सिवाय, जो उसके द्वारा जानबूझ कर किए गए कार्य या व्यतिक्रम के कारण हुए हों, ऐसी सभी हानियों और व्ययों के लिए अतिपूर्ति करेगा, जो उसके द्वारा अपने कर्तव्यों के निर्वहन में उपगत किए जाते हैं ।

(2) कोई निदेशक, निगम के किसी अन्य निदेशक के प्रति अथवा किसी अधिकारी या अन्य कर्मचारी के प्रति या निगम की ओर से सद्भावपूर्वक अजित या ली गई किसी सम्पत्ति या प्रतिभा के मूल्य या हक की किसी अपर्याप्तता या कमी अथवा अपने पद के कर्तव्यों के निष्पादन में या उसके सम्बन्ध में सद्भावपूर्वक की गई किसी बात के परिणामस्वरूप निगम को होने वाली किसी हानि या व्ययों के लिए उत्तरदायी नहीं होगा ।

रजिस्ट्रीकरण
फीस और
स्टाम्प शुल्क
से छूट ।

34. निगम द्वारा या उसकी ओर से इसके कृत्यों के निर्वहन के सम्बन्ध में निष्पादित सभी लिखतों पर स्टाम्प शुल्क और रजिस्ट्रीकरण फीस के संदाय की छूट होगी :

परन्तु स्टाम्प शुल्क के संदाय से छूट केवल ऐसी लिखतों के मामले में लागू होगी जो भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 (1899 का 2) की अनुसूची 1-अ में विनिर्दिष्ट है ।

विनियम
बनाने की
शक्ति ।

35. (1) धारा 36 के अधीन राज्य सरकार द्वारा बनाए गए नियमों के अधीन रहते हुए, बोर्ड, समय-समय पर, इस अधिनियम में अन्तर्निष्ठ उपबन्धों की प्रभावी बनाने के प्रयोजन के लिए ऐसे विनियम बना सकेगा जो इस अधिनियम और तद्धीन बनाए गए नियमों से असंगत न हों ।

(2) विशिष्टतया और पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे विनियम निम्नलिखित के लिए उपबन्ध कर सकेंगे—

(क) बोर्ड की बैठकों का समय और स्थान और ऐसी बैठकों के सम्बन्ध में

अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया, जिसके अन्तर्गत इस के कारवार के संव्यवहार के लिए आवश्यक गणपूर्ति भी है;

- (ख) वे शर्तें जो निगम ऋण देने या अन्य इन्तजाम करने में अधिरोपित कर सकेगा;
- (ग) ऋणों पर व्याज की दर;
- (घ) वे कर्तव्य जिनका प्रबन्ध निदेशक द्वारा पालन किया जायेगा;
- (ङ) निगम के अधिकारियों और कर्मचारियों के कर्तव्य, आचरण, वेतन, भत्ते और सेवा की शर्तों;
- (च) निगम के अधिकारियों और कर्मचारियों को शक्तियों और कृत्यों का प्रत्या-योजन;
- (छ) निगम के अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए भविष्य और अन्य लाभ निधियों का स्थापन और बनाए रखना; और
- (ज) साधारणतया, निगम के कार्यकलापों का दक्ष संचालन।

36. (1) राज्य सरकार, इस अधिनियम के सभी या किन्हीं प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए नियम अधिसूचना द्वारा, बना सकेगी।

नियम बनाने की शक्ति।

(2) विशिष्टतया और पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे नियम निम्नलिखित सभी या किन्हीं विषयों के लिए उपबन्ध कर सकेंगे, अर्थात्:—

- (क) धारा 2 के खण्ड (ख) के अधीन अत्योदय कुटुम्बों की पहचान के लिए प्रमाण नियतन;
- (ख) निदेशकों और उपाध्यक्ष की नियुक्ति के निबन्धन और शर्तें और उनको संदेय फीस और भत्ते;
- (ग) धारा 16 की उप-धारा (2) के खण्ड (4) के अधीन निगम द्वारा निष्पादित और निर्वहन किए जाने वाले कार्यक्रम और कृत्य;
- (घ) वह प्ररूप जिसमें प्रबन्ध निदेशक द्वारा प्रमाण-पत्र जारी किया जाएगा और वह प्रक्रिया जिसका धारा 24 के अधीन रकम अवधारित करने के लिए अनुपालन किया जाएगा;
- (ङ) वह प्ररूप और रीति जिसमें लेख रखे जाएंगे और तुलनपत्र और हानि तथा लाभ लेखा तैयार किया जाएगा; और
- (च) कोई अन्य विषय जिसे विहित किया जाना है या विहित किया जाए।

(3) इस धारा के अधीन बनाया गया प्रत्येक नियम, बनाए जाने के पश्चात् यथाशीघ्र, विधान सभा के समक्ष, जब वह सत्र में हो, कुल दस दिन की अवधि के लिए रखा जाएगा। यह अवधि एक सत्र में अथवा दो या अधिक आनुक्रमिक सत्रों में पूरी हो सकेगी। यदि उस सत्र के या पूर्वोक्त आनुक्रमिक सत्रों के ठीक बाद के सत्र के अवसान के पूर्व विधान सभा उस नियम में कोई परिवर्तन करने के लिए महमत हो जाए तो तत्पश्चात् वह ऐसे परिवर्तित रूप में ही प्रभावी होगा। यदि उक्त अवसान के पूर्व विधान सभा सहमत हो जाए कि वह नियम नहीं बनाया जाना चाहिए तो तत्पश्चात् वह निष्प्रभाव हो जाएगा। किन्तु नियम के ऐसे परिवर्तित या निष्प्रभाव होने से उसके अधीन पहले की गई किसी बात की विधिमान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

37. यदि इस अधिनियम के उपबन्धों को प्रभावी करने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है तो सरकार, राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा, ऐसे उपबन्ध बना सकेगी या ऐसे निदेश दे सकेगी जो इस अधिनियम के उपबन्धों से असंगत न हों, जो ऐसी कठिनाई को दूर करने के लिए इसे आवश्यक या समीचीन प्रतीत हों।

कठिनाई दूर करने की शक्ति।

